नं. जेड-14014/1/2021-जीसी एण्ड पार्लि. (ई-3010921)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 20.07.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: जून, 2023 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार - के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को जून, 2023 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोक्त।

अर्जुन राणा

(अर्जुन राणा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी माननीय सदस्य

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत के माननीय राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के माननीय प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
6. सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
7. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।

9. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. सचिव, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. सचिव, खान मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. सचिव, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. सचिव, व्यय विभाग, नई दिल्ली।
18. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
19. सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
20. सचिव, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
22. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी), भूमि संसाधन विभाग, को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीया राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथाउपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) के निजी सचिव।
3. माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा इस्पात) के निजी सचिव।

जून, 2023 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार - के संबंध में।

1. विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन)- भूआधार को 27 राज्यों में शुरू किया गया है, जिसमें चंडीगढ़, संघ राज्य क्षेत्र शामिल है जहां हाल ही में इसे आरंभ किया गया है। इसमें शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, बिहार, ओडिशा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, असम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, तमिलनाडु, पंजाब, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और लद्दाख हैं।

2. सचिव (भूमि संसाधन विभाग) ने दिनांक 06.06.2023 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक के तहत शूलहीन केक्टस की खेती और उसके आर्थिक उपयोग, विशेषतः बायो-गैस के उत्पादन, को बढ़ावा देने के लिए भूमि संसाधन विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा अन्य हितधारकों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक का आयोजन किया।

3. सचिव (भूमि संसाधन विभाग) तथा संयुक्त सचिव (भूमि विनियमन) ने नई दिल्ली में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीसीएस) की "भूमि और सम्पत्ति" उप-विषय पर कार्यशाला में भाग लिया। संयुक्त सचिव (एलआर) ने जीवन यापन में आसानी के संदर्भ में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

4. संयुक्त सचिव (एलआर) ने दिनांक 12-13 जून, 2023 को पुणे में आयोजित ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इन्फास्ट्रक्चर (डीपीआई) प्रदर्शनी के साथ प्रथम ग्लोबल डीपीआई सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का प्रयोजन वैश्विक समुदाय के लाभ हेतु डीपीआई के कार्यान्वयन पर अनुभवों और सर्वोत्तम कार्यकलापों को साझा करने और वैश्विक डीपीआई भंडारों (रिपाजिटरीज) का पता लगाने में सहायता करना था।

5. संयुक्त सचिव (वाटरशेड प्रबंधन) ने दिनांक 12.06.2023 और 21.06.2023 को विश्व बैंक सहायता प्राप्त रिवार्ड (आरईडब्ल्यूएआरडी) परियोजना पर विश्व बैंक के साथ दो समीक्षा बैठकों का आयोजन किया। रिवार्ड (आरईडब्ल्यूएआरडी) परियोजना पर दिनांक 27.06.2023 को राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) और इसकी भागीदार एजेन्सियों के साथ एक पृथक बैठक का आयोजन किया गया। संयुक्त सचिव (वाटरशेड प्रबंधन) ने डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई योजना के तहत व्यय, एमआईएस कार्यान्वयन और अमृत सरोवर की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 13.06.2023, 22.06.2023 और 28.06.2023 को राज्यों के साथ विडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से तीन बैठकों का आयोजन किया।

6. विभाग द्वारा दिनांक 21.06.2023 को शिवाजी स्टेडियम कार्यालय परिसर में स्थित विभाग के रिजूव वेलनैस सेंटर में 9वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2023 को मनाया गया जिसमें सचिव (भूमि संसाधन विभाग) ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योग सत्र में भाग लिया। विभाग द्वारा एक नियमित कार्यकलाप के रूप में प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को योग विशेषज्ञों के माध्यम से योग सत्रों का आयोजन भी किया जा रहा है।

7. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के तहत कुल 6382 {8214 (स्वीकृत) - 1832 (राज्यों को अंतरित)} परियोजनाओं में से अब तक 6376 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं (पूरी हो चुकी परियोजनाओं का 99.90%)। अभी तक 5841 परियोजनाओं की एंड लाइन मूल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

8. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के विभिन्न घटकों की प्रगति (संचयी) की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

i. 6,22,653 गांवों के भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया।
ii. 4,924 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्रीकरण का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया।
iii. 1,28,83,851 भूकर मानचित्रों/एफएमबी/टिप्पनों का डिजिटलीकरण पूरा किया गया।
iv. 4,081 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों का भूमि अभिलेखों के साथ एकीकरण का कार्य पूरा किया गया।
v. 3,326 तहसीलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना पूरी की गई।